

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 09 अगस्त, 2008

विषय:- श्रीमती भगवती कपिल पत्नी श्री सुरेश चन्द्र कपिल निवासी पटेल चौक हल्द्वानी जिला नैनीताल को बावत हल्द्वानी में रिक्त भू-खण्ड 30X40 फिट भूमि आवास हेतु पट्टे पर आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- २-2459/11-आर0 के0 खाम दिनांक 07.06.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती भगवती कपिल पत्नी श्री सुरेश चन्द्र कपिल निवासी पटेल चौक हल्द्वानी (नैनीताल) को आवासीय प्रयोजन हेतु हल्द्वानी में खेवट खाता संख्या-1 खाम इस्टेट-एक के खसरा संख्या-452 की राजकीय आस्थान की भूमि मध्ये 30X40 फिट अर्थात् 111.48 वर्गमीटर भूमि राजस्व अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या-258/16 (1)/73-रा-1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1 -1(60)/93-रा-1 दिनांक 12 सितम्बर, 97 के अनुसार वर्तमान बाजार दर से निकाले गये भूमि के मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा करने तथा नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- 2- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा।
- 3- नजराने की धनराशि इस शासनादेश के निर्गत होने के उपरान्त तत्काल अथवा अधिकतम 03 (तीन) माह के भीतर जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
- 4- भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 5- प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्राण्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए ही होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा, तथा सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

- 6- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।
 - 7- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।
 - 8- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त बिन्दु सं० 01 से 07 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
 - 9- उक्त आवंटन किसी नीति के अधीन नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसे अन्य प्रस्तावों पर इसे उदाहरण स्वरूप नहीं लिया जा सकता है।
- 2- उक्त आदेशों का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन०एस० नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या /18(1)/08-7(42)/2008 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
- 3- श्रीमती भगवती कपिल पत्नी श्री सुरेश चन्द्र कपिल निवासी पटेल चौक, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल।
- 4- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।